पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकवादी मारे गए

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, तीनों लश्करे तैयबा के ए श्रेणी के आतंकवादी थे

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में घोषणा की कि पहलगाम आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले तीनों आतंकवादी सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गये।

शाह ने लोक सभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान कल पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादी सुलेमान, अफगान और जिब्रान सैन्य बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गये। उन्होंने बताया कि सुलेमान आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा का ए श्रेणी आतंकवादी और तथाकथित कमांडर था। अफगान और जिब्रान भी लश्करे तैयबा से जुड़े हुए ए श्रेणी के आतंकवादी थे।

उन्होंने बताया कि मारे गये तीनों आतंकवादियों के पहलगाम घटना में शामिल होने की पुष्टि इन्हें पनाह देने वालों से करायी गयी है। पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियारों से निकले खोखे की मिलान कर लिया गया है और इसकी पुष्टि हो गयी है कि इन आतंकवादियों के कब्जे से बरामद हथियार ही पहलगाम हमले में इस्तेमाल किये गये थे। शाह ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन आतंकवादियों को पहलगाम घटना के बाद शरण और भोजन देने वालों को गिरफ्तार किया था। उनसे इन आतंकवादियों की पहचान करायी गयी है। इन आतंकवादियों के पास पाकिस्तान निर्मित चाकलेट बरामद की गयी थी।

> ■ शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार हर आतंकी हमले का करारा जवाब देती है।

उन्होंने कहा कि वह पहलगाम हमले में मारे गये पर्यटकों के पीड़ित परिजनों से कहना चाहते हैं कि पहलगाम आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को सैन्य बलों ने सोमवार को मार गिराया है और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया था।

शाह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित नौ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के अलावा पाकिस्तान के 11 एयरबेस क्षतिग्रस्त किये गये इनमें नौ तो पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के छह राडार सिस्टम ध्वस्त किये गये। इस तरह पाकिस्तान के सेना के कमर तोड़ दी गयी तो उसके पास युद्ध विराम करने की गुहार लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की पूर्व में की गयी गलतियों के कारण ही पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आतंकवादी हमलों का पाकिस्तान को सटीक जवाब नहीं जाता था लेकिन अब मोदी सरकार हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देती है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं मे कमी आयी है। पथराव की घटनायें बंद हो गयी हैं। वहां आतंकवादी इकोसिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब घाटी में बंद आहूत नहीं किये जाते।

सुप्रीम कोर्ट बिहार की मतदाता सूचि पर फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेगा

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में 65 लाख मतदाताओं के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंकाओं पर मंगलवार को मौखिक रूप से फिर कहा कि यदि ऐसा हुआ तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की आशंका पर यह आश्वासन दिया। पीठ के समक्ष अधिवक्ता भूषण ने निर्वाचन आयोग के इस बयान का

> ■ मतदाताओं को मतदाता सूचि से बाहर किये जाने पर कार्यवाही का आश्वासन।

जिक्र किया कि 65 लाख लोगों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं। भूषण ने कहा कि इससे उन मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने की आशंका है।

शीर्ष अदालत बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, सुनवाई 12 और 13 अगस्त को करने वाली है।

खड़गे पर नड्डा के बयान से राज्यसभा में बवाल मचा

बाद में नड्डा ने अपने शब्द वापस लिए और माफी मांगी

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। दरअसल, खड़गे की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर कही गईं बातों पर नड्डा ने आपत्ति जताई और कुछ ऐसा बोल गए कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद नड्डा ने अपने शब्द वापस ले लिए। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसी बातों का इस्तेमाल किया है, वी ठीक नहीं है।

दरअसल, राज्यसभा में खड़गे के बयान पर कुछ आपत्तियों के साथ जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया। नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता ने लंबा वक्तव्य दिया, लेकिन उनके कद के हिसाब से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो उनके स्तर के नहीं थे, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की। मैं उनकी

> ■ लेकिन नड्डा ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता को प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखना चाहिये था।

तकलीफ समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें 11 साल से विपक्ष में बिठाए रखा है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये हमारे लिए भी और देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आपकी चिंता पार्टी के लिए इतनी है कि उसमें देश का विषय भी गौण हो जाता है। आप भावावेश में आकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं।

इसके बाद सदन में हंगामा हो गया और कांग्रेस सांसदों ने असंसदीय शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई। इस पर नड्डा ने ये शब्द कार्यवाही से हटाने की अपील की। इससे सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए बाधित हुई। खरगे ने बयान को लेकर नड्डा से माफी की मांग की। इस पर नड्डा ने कहा कि आपको अगर ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप भी भावावेश में इतना बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख पाए।

ट्रंप ने रुस को 10-12 दिन का नया अल्टीमेटम दिया

लंदन, 29 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन युद्धविराम पर सहमत होने के लिए रूस को "10 या 12 दिन" की एक नयी, छोटी समय सीमा दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस अवधि को "बेहद महत्वपूर्ण" बताया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब और इंतज़ार करने का "कोई कारण" नहीं है, क्योंकि शांति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। विदित हो कि दो सप्ताह पहले ट्रम्प ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के पास युद्ध समाप्त करने के लिए 50 दिन हैं, अन्यथा रूस को कड़े आयात शुल्कों का सामना करना पड़ेगा।

> ■ रुस ने कहा, ट्रंप के अल्टीमेटम मॉस्को में काम नहीं करते।

कल स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रम्प ने यूक्रेन में चल रही गतिविधियों पर फिर से अपनी असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें "अब बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है"। सोमवार के ताज़ा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी सांसद आंद्रेई गुरुल्योव ने कहा है कि ट्रम्प के अल्टीमेटम "अब काम नहीं कर रहे..न अग्रिम मोर्चे पर, न मॉस्को में" और रूस के पास "हथियारों, सिद्धांतों और इच्छाशक्ति" की ताकत है।

विदित हो कि शांति के लिए रूस ने शांति के लिए जो शर्तें रखीं हैं वे यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को अस्वीकार्य हैं।

खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को पिपलोदी भेजा

नई दिल्ली, 29 जुलाई। राजस्थान में झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने की घटना में सात बच्चों की मौत के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी नेताओं को वहां जाकर संबंधित पहलुओं की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेन्द्र पाल गौतम, अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और राजस्थान प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष बाबूलाल सांखला और अनुसूचित जनजाति विभाग के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा बुधवार को झालावाड़ का दौरा करेंगे। ये नेता पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंपेंगे।

> ■ ये नेता पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे।

उल्लेखनीय है पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद, कई अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पहलगाम और ऑपरेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाई-वोल्टेज प्रचार में विश्वास करती है, लेकिन जब जवाब देने की बात आती है, तो खामोश हो जाती है। कश्मीर के लोगों को यह जानने का हक है कि उनके नाम पर क्या किया जा रहा है।"

तृणमूल कांग्रेस की सयानी घोष ने सरकार पर कश्मीर को राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा: यह सरकार संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी दिखाने में असफल रही है। उन्होंने कहा, हम लोकतंत्र हैं प्रचार मशीन नहीं। सरकार को पता होना चाहिए शासन का अर्थ जन सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा है।

विपक्ष का यह तीखा हमला ऐसे समय में हुआ है, जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस घटना ने फिर से यह बहस छेड़ दी है कि क्या सरकार की कश्मीर नीति और खुफिया एजेंसियों के बीच पर्याप्त समन्वय है। हालांकि, सरकार द्वारा विपक्ष के इन आरोपों पर विस्तृत जवाब सत्र के बाद में देने की संभावना है, लेकिन सोमवार को हुई बहस ने संसद में विपक्ष की एकता और सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही पर एक संयुक्त सवाल खड़ा कर दिया है।

प्रधानमंत्री से 35 मिनट मीटिंग ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, भजनलाल ने एक बयान भी जारी किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे अपनी स्थिति को लेकर आश्वस्त हैं। अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री भजनलाल ने दूरदर्शी नेतृत्व व निरन्तर सहयोग के लिये प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में राजस्थान निरंतर विकास सभी बाधाओं को पार करता जा रहा है और नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रभु राम की प्रतिमा भी भेंट की।

डिंपल यादव पर कमैंट करने वाले मौलाना को कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा

नोएडा, 29 जुलाई। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा है। बताया जा रहा है कि यह वाकया नोएडा में एक निजी चैनल के स्टूडियो में हुआ है और अब घटना का वीडियो वायरल हुआ है। मौलाना ने कहा सपा नेता मोहित नागर ने उन्हें थप्पड़ जड़ा है और इससे उनके समर्थक भड़क गए हैं।

> ■ मौलाना साजिद रशीदी ने नोएडा में दो सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमला करने की शिकायत दर्ज की।

ज्ञातव्य है कि रशीदी ने डिंपल के पति और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव और दूसरे सपा सांसदों के साथ हाल ही में एक मस्जिद में मुलाकात करने जाने पर टिप्पणी की थी। मौलाना ने हाल ही में एक टेलीविजन बहस के दौरान मैनपुरी की सांसद के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। जिसपर स्थानीय निवासी प्रवेश यादव ने रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

छात्रसंघ चुनाव पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। वहीं लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत, हर साल छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए। कमेटी की सिफारिश के अनुसार, सत्र शुरु होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। याचिका में कहा गया कि विश्वविद्यालय ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है और यदि उसकी अवहेलना होती है तो नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है। इसके बावजूद, विवि प्रशासन की ओर से ही इस कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना जा रहा। याचिका में कहा गया कि कमेटी की सिफारिश होने तथा सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे मूलभूत अधिकार घोषित करने के बावजूद, भी राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षिणक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

मोदी ने चोल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्नाद्रमुक के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाए हैं।

पहले यह धारणा थी कि भाजपा अन्नाद्रमुक पर दबाव बना रही है, लेकिन अब अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि यह साझेदारी स्वैच्छिक और सम्मानजनक हो सकती है।

मोदी की यात्रा के दौरान, अन्नाद्रमुक ने प्रधानमंत्री के तिरुचि रोड शो को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संगठित किया, जो यह संकेत देता है कि पार्टी अब भाजपा के साथ काम करने को लेकर अपनी पुरानी झिझक छोड़ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेता कई बार तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इन कार्यक्रमों में अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं की भागीदारी दोनों पार्टियों के बीच विश्वास और समन्वय को और मजबूत कर सकती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य भाजपा अध्यक्ष नैयनार नागेन्द्रन ने संकेत दिया है कि वह ईपीएस और अन्नाद्रमुक नेताओं को उनके राज्यव्यापी दौरे के दौरान भोजन पर आमंत्रित करेंगे, जो अगले महीने शुरू होने वाला है।

'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास लगभग 34,000 मामले लंबित'

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन ने पत्रकारों को जानकारी दी

हैदराबाद, 29 जुलाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने मंगलवार को बताया कि आयोग के पास वर्तमान में 34,685 से अधिक मामले लंबित हैं।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने हैदराबाद स्थित डॉ. एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान में आयोग के दो दिवसीय शिविर के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आयोग देश भर में मानवाधिकार उल्लंघन संबधित मामलों पर सक्रिय रूप से स्वत: संज्ञान ले रहा है।

उन्होंने कहा "2021 में हमने ऐसे 17 मामले उठाए, 2022 में यह संख्या बढ़ कर 60, 2023 में 107 और 2024 में 105 हो गई। अब 2025 के मध्य तक यह संख्या 50 से अधिक हो गयी है।"

आयोग ने हैदराबाद में शिविर के दौरान दो खंडपीठों और एक पूर्ण आयोग सत्र के माध्यम से 87 मामलों का निपटारा किया जिनमें क्रमश: 36 और 51 मामले खंडपीठों द्वारा और 19 मामले पूर्ण पैनल द्वारा निपटाए गए।

> ■ जस्टिस राममूर्ति ने हैदराबाद के डॉ.एम.सी.आर. मानव संसाधन विकास संस्थान में दो दिवसीय शिविर में शिरकत की।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आयोग ने हिरासत में हुई मौतों के मामलों में मुआवज़े के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं और अन्य चार हफ्तों के भीतर होने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा "तेलंगाना में हमारे पास केवल 780 मामले लंबित हैं। इनमें पुलिस हिरासत में हुई मौतों के चार मामले और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 30 मामले शामिल हैं।"

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा "हम समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखते हैं। जब भी हमें हिरासत में मौत, खुले नालों में गिरने से मौत, स्कूलों या छात्रावासों में लापरवाही के कारण आत्महत्या जैसी घटनाओं का पता चलता है, हम कार्रवाई करते हैं। मीडिया हमें समाज की नब्ज़ पढ़ने में मदद करता है।"

उन्होंने कुछ हालिया मामलों का हवाला दिया जिनमें एक किशोर को गलत तरीके से 40 दिनों की जेल हुई थी। इस बाबत उसे मुआवज़ा दिया गया। इसी प्रकार स्कूलों में बड़े पैमाने पर खाद्य विषाक्तता के मामले शामिल हैं जिनकी जाँच की जा रही है।

अध्यक्ष ने एक उल्लेखनीय हस्तक्षेप का भी उल्लेख किया जहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार से अपहृत एक लड़की का पता लगाने और उसे बचाने में मदद की। वह राजस्थान में मिली थी और सीमा पार मानव तस्करी के लिए भेजी जाने वाली थी।

वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांकों में भारत की रैंकिंग पर न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने इस रैंकिंग में असमानताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि आयोग नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है।

उन्होंने कहा "हम यहाँ केवल बोलने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ सुनने के लिए हैं। मीडिया की, कार्यकर्ताओं की और अधिकारों के उल्लंघन का सामना करने वालों की हम सुनेंगे। यह सहयोग वास्तविक बदलाव की कुंजी है।"

लैफ्टिनैंट जनरल प्रतीक ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात की

श्रीनगर, 29 जुलाई। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मंगलवार को यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी दी।

इस मौके पर उनके साथ 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी मौजूद थे।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल ने ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस को बधाई दी। चुनौतीपूर्ण दाचीगाम के जंगल में चलाए गए इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन के परिणामस्वरूप पहलगाम के जघन्य आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया हो गया।

> ■ प्रतीक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं।
>
> ■ उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को ऑपरेशन महादेव की जानकारी दी।

उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दक्षिण कश्मीर के दाचीगाम के जंगल क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी था। इस क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की लगातार खबरें मिल रही थीं। हाल ही में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, विशेष टीमों को सक्रिय किया गया था। इसके बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खुफिया एजेंसियों की सहायता से एक संयुक्त अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया हो गया।

बस-ट्रक भिंड़त...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सड़क पर गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस दो सौ मीटर आगे जाकर ईंटों के ढेर से टकराकर रुक गई। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। हादसा मंगलवार सुबह 5 बजे देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास नावापुरा गांव में हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। कांवड़ियों के झोले और सामान बस में लटके दिख रहे हैं। हादसे में बस का ड्राइवर सीट समेत नीचे गिर गया। 100 मीटर तक बस बिना ड्राइवर के चली।

दिल्ली-एनसीआर में अगले सात दिन भारी बारिश की आशंका

मौसम विभाग ने रैड अलर्ट जारी किया

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य राज्यों में अगले सात दिनों में बारिश होने का अनुमान जताया है।

> ■ दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भी तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

आईएमडी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश होने के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह से तेज बारिश होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज पूरे दिन बारिश रुक-रुक बारिश होने का अनुमान जताया था, जब सुबह शुरू हुई तेज बारिश के कारण आईटीओ, धौला कुआं, नारायणा, पटेल नगर, विजय चौक, जंगपुरा, आर के पुरम, लाजपत नगर, तालकटोरा रोड, रफी मार्ग, वजीरपुर, भजनपुरा और रोहिणी से लेकर लगभग पूरे दिल्ली के इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात जाम हो गया और वाहनों की लम्बी कतारें देखी गयी है। वहीं नोएडा में कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया।

क्षेत्रीय मौसम केंद्र के अनुसार अगले सात दिनों तक, यानी तीन अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहने के आसार है। कई इलाकों के लिए रैड अलर्ट जारी किया गया है।

नेतृत्व सिर्फ श्रेय लेना नहीं होता, जिम्मेवारी भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ज़्यादातर लोगों के पास सुरक्षा कवर है, लेकिन उस दिन पहलगाम में 26 लोग अपने परिवार के सामने मारे गए। वहां मौजूद किसी के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर लें, सच नहीं छुपा सकते।"

उन्होंने सवाल किये, "बैसारन में एक भी सुरक्षा जवान क्यों नहीं था? क्या नागरिकों की सुरक्षा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं है?"

उन्होंने कहा, "आज गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी मां के आंसुओं की बात की। मैं जवाब देना चाहती हूं, मेरी मां के आंसू तब गिरे थे, जब आतंकवादियों ने मेरे पिता को मार दिया था। आज जब मैं उन 26 लोगों की बात करती हूं, तो इसलिए, क्योंकि मैं उनका दर्द समझती हूं।"

कांग्रेस महासचिव ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार जिम्मेदारी से भागती है। "कल रक्षा मंत्री (राजनाथ सिंह) ने एक घंटे का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बातें कीं, लेकिन उन्होंने एक बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। 22 अप्रैल, 2025 को 26 देशवासी मारे गए, लेकिन यह हमला कैसे और क्यों हुआ?"

प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार हर राष्ट्रीय त्रासदी को राजनीतिक मुद्दा बना देती है। "यह सरकार हर बार सवालों से भागती है, देश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके दिलों में जनता के लिये कोई जगह ही नहीं है। इनके लिए सब कुछ राजनीति है, प्रचार है।"

प्रियंका ने अपने भाषण में कहा, "साहब, आप इतिहास की बात करते हैं, मैं वर्तमान की बात करूंगी। आप हमेशा बहाने ढूंढ़ते हैं, पूरी (गांधी) फैमिली को गिनवाते हैं, आप 11 साल से सत्ता में हैं। कल गौरव गोगोई ने गृह मंत्री से सवाल किया, क्या वह आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? रक्षा मंत्री राजनाथ जी सिर हिला रहे थे, लेकिन गृह मंत्री हँस रहे थे।

जब प्रियंका ने लोकसभा में अपना पहला नाम पढ़ा तो सत्तापक्ष की ओर से 'हिंदू' के नारे लगे। उन्होंने जवाब में कहा, "भारतीय"।

प्रियंका ने लोकसभा में "ऑपरेशन सिंदूर" पर चर्चा के दौरान कहा, "उस दिन 26 भारतीय परिवार बर्बाद हो गए। उनके लिये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर लें, इस सच्चाई को नहीं छुपा सकते। हम सब उन परिवारों के प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें सच्चाई जानने का हक है।" उन्होंने कहा, "यह सरकार सिर्फ जवाब देने से बचने की कोशिश करती है।"

जब गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों के मारे जाने का विवरण दिया, उन्होंने, हमेशा की तरह, 1948 से लेकर 1962 की भारत-चीन लड़ाई तक की बातें कीं और नेहरू के कार्यकाल पर आरोप लगाए थे।

उन्होंने 2004 से 2014 के बीच यूपीए शासन के दौरान पूरे देश में हुए 25 आतंकी हमलों की सूची भी पेश की थी।

प्रियंका ने शाह पर पलटवार करते हुए कहा, "उन्होंने यूपीए शासन के दौरान हुए 25 हमलों की बात की। वहीं, टीआरएफ आतंकी संगठन, जिसने पहलगाम हमले की ज़िम्मेदारी ली, उसने अप्रैल 2020 से लेकर अब तक कश्मीर में ही 25 हमले किए हैं। मुंबई हमलों के दौरान सभी आतंकियों को (एक को छोड़कर) तुरंत मार दिया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था।"

उन्होंने कहा, "हर बार जब भी कोई घटना होती है, वे मेरे परिवार के लोगों के नाम गिनाने लगते हैं। आप 11 साल से सत्ता में हैं। यह समय आप की सत्ता के दौरान हो रही घटनाओं की जिम्मेदारी लेने का है।

पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे हमलों का ज़िक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, "ये सभी हमले तब हुए, जब मोदी प्रधानमंत्री थे। उस समय के गृह मंत्री आज रक्षा मंत्री हैं। मणिपुर को आज के गृह मंत्री के कार्यकाल में जलाया गया। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया।"

वायनाड से पहली बार सांसद बनीं प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है।

उन्होंने कहा, "बम धमाके सुर्खियां बनते हैं, लेकिन असली कहानी चूक में निहित होती है। किसी ने जवाब नहीं दिया कि 22 अप्रैल को क्या हुआ और क्यों हुआ? बैसारन वैली में एक भी सैनिक क्यों नहीं था? वहाँ मेडिकल सुविधा क्यों नहीं थी? उन्होंने कहा, (शाह) इतिहास के पन्नों में चले गए। नेहरू, इंदिरा गांधी, मेरी मां के आंसू, लेकिन उन्होंने (असली) सवाल का जवाब नहीं दिया।

प्रियंका ने कहा, "लीडरशिप का मतलब सिर्फ श्रेय लेना नहीं होता, ज़िम्मेदारी लेना भी होता है। यह कांटों का ताज है, सोने का नहीं। मोदी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना चाहते हैं। वे खिलाड़ियों के ओलंपिक पदक जीतने का श्रेय भी लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से कोई नेता नहीं बनता। जवाबदेही भी ज़रूरी है। इस सरकार की राजनीतिक कायरता इस हद तक है कि कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं।

प्रियंका ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य अभी भी अधूरा है।

उन्होंने कहा, "अगर ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो यह अब भी अधूरा है। पाकिस्तान के जनरल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच किया। पाकिस्तान आज संयुक्त राष्ट्र के एंटी-टैरर ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा है, इससे (ऑपरेशन सिंदूर के) उद्देश्य को आघात पहुंचा है।

प्रियंका गांधी का आज का लोकसभा भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उनका भाषण यूट्यूब समेत, कई सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय :